भारत जोड़ो यात्रा का झालावाड़ में तीसरा दिन

खेल संकुल से निकली यात्रा, आज कोटा जिले में प्रवेश करेगी

- झालावाड़ में यात्रा जब दुष्यंत सिंह के कार्यालय और भाजपा कार्यालय के बाहर से गुजरी तो राहुल गांधी ने वहां एकत्रित भाजपा कार्यकर्ताओं का भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

झालावाड़, 6 दिसम्बर (निसं)। भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को दूसरे दिन झालावाड़ के खेल संकुल से शुरू हुई जो मेडिकल कॉलेज, मामा भांजा चौराहा से कोटा रोड स्थित देवरी घटा पहुंची। देवरी घटा में दोपहर के लंच बाद तीन किलोमीटर आगे कोटा जिले की रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र के सुकेत से यात्रा शुरू हुई और 9 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद हीरिया खेड़ी पहुंची। यहां से भी 17 किलोमीटर आगे खेल मैदान मोरु कला में रात्रि विश्राम हुआ।

झालावाड़ शहर में अल सुबह ही लोग राहुल गांधी की यात्रा को देखने के लिए सड़कों के आसपास जमा होने लग गए। जहां-जहां से यात्रा गुजरी वहीं हर चौराहे और सड़कों पर राहुल गांधी और उनकी यात्रा को देखने के लिए भीड़ जमा थी। शहर में लोगों द्वारा जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं कोटा रोड स्थित केजीएन नर्सिंग कॉलेज के सामने कॉलेज संचालक सलीम खान ने राहुल गांधी और यात्रा का स्वागत किया, इस दौरान बाड़मेर से आए कलाकारों ने "केसरिया बालम आवो पधारो म्हारे देस" लोक गीत गाकर राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत किया। स्वागत करने वालों में सलीम खान के अलावा राजेंद्र सिंह सलूजा शाहनवाज खान, सोहेल खान, कांग्रेस नेता अरबाज खान, फराज खान शामिल थे।

खेल संकुल से रवाना होकर यात्रा झालावाड़ में कोटा रोड पर स्थित भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह के कार्यालय के आगे से गुजरी तो सांसद दुष्यंत सिंह के कार्यालय की छत पर भाजपा कार्यकर्ता खड़े थे। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस दिया। जब यात्रा भाजपा कार्यालय के बाहर से यात्रा गुजरी तो राहुल गांधी ने पहले हाथ हिलाया और उसके बाद कार्यकर्ताओं की ओर फ्लाइंग किस दिया। राहुल गांधी ने अपने साथ चल रहे सचिन पायलट और राजस्व मंत्री रामलाल जाट को भी अभिवादन करने के लिए कहा, इसके बाद दोनों नेताओं भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

यात्रा में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला वाला सहित प्रदेश के कई मंत्री और विधायक भी साथ चले।

मंत्री विधायकों को राहुल गांधी की यात्रा से ज्यादा लगाव नहीं

अधिकांश मंत्री- विधायक यात्रा की अगवानी करने के बाद अगले दिन ही वापस लौट गए, भीड़ के मामले में भी बहुत ज्यादा सफल नहीं दिखे शुरुआती 2 दिन

- यात्रा के दौरान झालावाड़ में भाजपा कार्यालय से युवकों ने लगाए मोदी के नारे, तो राहुल गांधी ने फ्लांइग किस देकर किया अभिवादन।
- सचिन पायलट जहां यात्रा में लगातार पैदल चल रहे हैं, वहीं, मुख्यमंत्री गहलोत कुछ पैदल, तो कुछ काफिले के साथ कार में सफर कर रहे हैं।
- दूसरे दिन राहुल गांधी ने विधायक वेद सोलंकी को बुलाकर लंबी चर्चा की।

जयपुर, 6 दिसम्बर (का.प्र.)। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में सबसे सफल यात्रा के तौर पर निकालने की बातें हो रही थी, लेकिन यात्रा के दूसरे दिन ही लगने लगा है कि यात्रा को लेकर राजस्थान के नेताओं में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। राजस्थान के अधिकांश मंत्री और विधायक 2 दिन से यात्रा के दौरान नदारद दिख रहे हैं। जो मंत्री विधायक यात्रा की अगवानी के लिए आए थे,वे भी वापस लौट चुके हैं। कुछ एक मंत्री और विधायकों को छोड़ दें,तो अधिकांश मंत्री - विधायक नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यात्रा में लगातार बने हुए हैं और कुछ दूर चलने के बाद वे अपने काफिले के आगे पहुंच जाते हैं। बताया जाता है कि इस कवायद के पीछे कारण यह है कि वह नहीं चाहते कि दूसरे पक्ष के विधायक या आम आदमी राहुल गांधी तक ज्यादा पहुंच बना पाए।

दूसरी ओर सचिन पायलट अधिकांश समय राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कभी पैदल तो कभी काफिले के साथ आगे जाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं।

यात्रा में पहले दिन कुछ विधायकों को तवज्जो मिली थी, तो कुछ को फटकार मिली थी। वहीं दूसरे दिन चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को बुलाकर राहुल गांधी ने चर्चा की। बताया जाता है कि वेद प्रकाश सोलंकी ने एससी - एसटी से जुड़े मुद्दों के साथ ही अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर बात की। इस दौरान राहुल गांधी और वेद प्रकाश सोलंकी करीब 6 - 7 मिनट तक लगातार बातचीत करते रहे। जिस समय सोलंकी बात कर रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी के एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चल रहे थे। वेद सोलंकी को सचिन पायलट कैंप का सबसे मुखर विधायक माना जाता है। अन्य विधायकों की बात करें, तो जोधपुर संभाग से जहां दिव्या मदेरणा मध्य प्रदेश से ही यात्रा के साथ बनी हुई है, वही संभाग के दूसरे विधायक मदन प्रजापत नंगे पांव लगातार यात्रा में चल रहे हैं।

इधर राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा दूसरे दिन कोटा के हिरिया खेडी में पूरी हुई।

शाम करीब छह बजे 22.5 किलोमीटर का सफर पूरा हुआ। यहां से आगे राहुल गांधी गाडियों से दरा के मोरू कला पहुंचे, जहां रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है।

सुबह यात्रा की शुरुआत में झालावाड में राहुल गांधी मुख्य चौराहे से निकल कर जा रहे थे। उसके बाद भाजपा कार्यालय तथा सांसद दुष्यंत सिंह के निजी कार्यालय के सामने से निकले, उसी दौरान वहां छत पर खडे कुछ युवकों ने मोदी - मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन राहुल गांधी इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और जो युवा नारे लगा रहे थे, उनकी तरफ फ्लाइंग किस करते हुए उनका अभिवादन भी किया।

यात्रा के दौरान एक छोटी सी दुर्घटना हुई और यात्रा का कवरेज करने के लिए उड़ाए गए ड्रोन कैमरा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के कंधे पर गिर गया, जिससे उन्हें हल्की चोट लगी। इसके कारण खाचरियावास को यात्रा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। खाचरियावास को यह चोट उसी कंधे पर आई है जिसका कुछ समय पूर्व उन्होंने ऑपरेशन कराया था। इससे पहले मंगलवार सुबह यात्रा के पहले फेज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि गुजरात चुनाव में भाजपा ने सारी हदें पार कर दीं। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन पीएम मोदी ने रोड शो में भाजपा का प्रचार किया।

कांग्रेस विधायकों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देकर 91 विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय करने का आग्रह किया था। इसके बावजूद भी स्पीकर ने अब तक इन इस्तीफों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है। याचिका में कहा गया कि यदि कोई विधायक इस्तीफा स्वयं पेश करता है तो विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के तहत स्पीकर के पास इस्तीफा स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता। सिर्फ इसके लिए जांच की जा सकती है कि इस्तीफा स्वैच्छिक और जेन्युइन है या नहीं। याचिका में यह भी कहा गया कि यह असंभव है कि इतनी बडी संख्या में विधायकों से जबरन इस्तीफों पर हस्ताक्षर करवाए गए हों या उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हों।

विधायकों के इस्तीफे देने के चलते सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है। इसके बावजूद भी इस्तीफा देने वाले मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सहित अन्य सरकारी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। याचिका में गुहार की गई है कि इस्तीफा देने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और बतौर विधायक इनका विधानसभा में प्रवेश से रोका जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि स्पीकर के समक्ष बसपा से दल बदल कर कांग्रेस में आए विधायकों का मामला लंबित है। ऐसे में उन्हें अंदेशा है कि इन विधायकों के इस्तीफों पर भी स्पीकर निर्णय नहीं करेंगे। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने स्पीकर और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

इस्तीफों पर निर्णय नहीं करने को चुनौती देने वाली इस याचिका की ड्राफ्टिंग अधिवक्ता हेमंत नाहटा की ओर से की गई। वहीं सुनवाई के दौरान भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड ने अपना पक्ष स्वयं रखा। एक अधिवक्ता की तरह पैरवी करने पर कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाई दी और नियमित वकालत करने की बात कही।

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दशक में, भाषाई आधार पर हुये राज्यों के पुनर्गठन के दौरान, यह नगर कर्नाटक को दे दिया गया था। "कर्नाटक रक्षण वेदिके" से सम्बद्ध प्रदर्शनकारी एकाएक हिंसा पर उतर आये क्योंकि बेलागावी विवाद अन्दर ही अन्दर खदबदा रहा था। आग में घी डालने का काम करते हुये, कर्नाटक भी महाराष्ट्र के कुछ गाँवों पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है।

प्रसंगवश बता दे कि महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमला बोलते हुये कहा कि भाजपा ही इस विवाद को इस स्थिति तक लाई है क्योंकि दोनों ही राज्यों में, वह सत्ता पर काबिज है। वरिष्ठ एन.सी.पी. नेता शरद पवार ने भाजपा तथा महाराष्ट्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुये कहा, "अगर महाराष्ट्र की बसों और ट्रकों पर हमले नहीं रूके, तो उन्हें (एन.सी.पी.) को कोई अलग रूख अपनाना पड़ेगा। पूर्ववर्ती गठबन्धन सरकार अब तक संतुलित रूख अपनाती आ रही थी।" एक ट्वीट में, महाराष्ट्र के इस दिग्गज नेता ने कहा कि अगर आगे कुछ भी होता है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई जिम्मेदार ठहराये जायेंगे। अगर हमले नहीं रूके तो वे स्वयं बेलगाँव जायेंगे। पवार ने दोनों मुख्यमन्त्रियों से अपील की कि वे साथ-साथ बैठकर, इस मुद्दे का समाधान तलाशे।

मंगलवार को, महाराष्ट्र ने एक कदम पीछे हटाते हुये, अपने उन दो मन्त्रियों को रोक लिया, जो विवादित स्थल पर जाने वाले थे क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह आशंका व्यक्त की थी कि मन्त्रियों के दौरे से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। जहाँ व्यावसायिक स्तर पर ये सब कदम उठाये जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ, सर्वोच्च न्यायालय भी इसी विषय से सम्बन्धित दायर की जा चुकी एक याचिका पर विचार कर रहा है।

वस्तुतः महाराष्ट्र के साथ चल रहे विवाद को लेकर, बेलागावी में हिंसा उस समय भड़की जब कन्नड़-झंडा लहरा रहे एक विद्यार्थी पर कुछ मराठी छात्रों ने हमला बोल दिया था।

16 दिसम्बर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बीसीआई के तीन अक्टूबर के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी थी। बीसीआई ने तीन अक्टूबर को आदेश जारी कर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित अन्य अधिवक्ता संगठनों के चुनावों को आगामी आदेश तक रोक दिया था। एकलपीठ ने बी.सी.आई. के इस आदेश की क्रियान्विति पर स्टे लगा दिया था। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने कहा कि बीसीआई के समक्ष कोई वोटर लिस्ट ही नहीं थी। ऐसे में उनकी ओर से चुनाव पर रोक लगाने का आदेश देना गलत था। इसके बाद खंडपीठ ने दोनों अपीलों को खारिज कर दिया।

ऐलन मस्क और वाइट हाउस के बीच जंग

- वाइट हाउस की प्रैस सचिव ने कहा कि, ट्विटर और वाइट हाउस के बीच जो कुछ भी चल रहा है वह अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।

वाशिंगटन, 6 दिसंबर (वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास तथा मुख्य कार्यस्थल 'व्हाइट हाउस' की प्रेस सचिव कराइन जीन-पियरे ने कहा है कि ट्विटर अधिकारियों और बाइडेन प्रशासन के बीच उच्च स्तरीय मिलीभगत दिखाने वाले खुलासे देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं।जीन-पियरे ने कहा, ट्विटर अधिकारियों और बाइडेन प्रशासन के बीच के जो कुछ भी चल रहा है वह देशवासियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर रोष, घृणा और सामाजिक तनाव फैलानी वाली प्रतिबंधित पुरानी सामग्री को कैसे रख सकता है। दरअसल, ट्विटर कर्मचारियों के शुक्रवार को लीक हुए ईमेल से पता चला कि सोशल मीडिया अधिकारियों ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर यह झूठा दावा किया था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के पुत्र हंटर बाइडेन के लैपटॉप से निकाली गई फाइलें एक रूसी विघटन अभियान की सामग्री थी। स्पूतनिक के पत्रकार जॉन किरियाकौ ने बताया कि खोजी पत्रकार मैट तैब्बी को लीक हुए ईमेल ट्विटर के नए मालिक ऐलन मस्क से प्राप्त हुए हैं।

डॉ. पूनिया का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपराधों की आग में झुलस रहा है, आज 8 लाख 31 हजार मुकदमे इसकी बानगी है, महिलाओं के प्रति सर्वाधिक 37 प्रतिशत अपराध, 27 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 38 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध यह पराकाष्ठा है।प्रतिदिन प्रदेश में औसतन 17 बलात्कार और 7 हत्याएं होती है, यह राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्या वो प्रदेश की महिलाओं के लिए लड़ने के लिए आएंगी, 1 लाख 50 हजार से ज्यादा मुकदमे महिलाओं के अपराधों के प्रति दर्ज हुए हैं, बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की 26 हजार से ज्यादा घटनाएं हुई हैं।

मेरा आज राहुल गांधी से दूसरा सवाल है, भले ही वह राजनीतिक पर्यटन के लिए यहां आए हैं, लेकिन कम से कम अपने कांग्रेस शासन की सरकार की सुध तो लेते, राजस्थान की जनता को अपराधों से मुक्ति कब दिलाएंगे, महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और बच्चियों को न्याय कब दिलाएंगे।

'तू डाल-डाल मैं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चरमरा जाएगी।

यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाए थे, तथापि इन प्रतिबंधों का ज्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि युद्ध के बाद तेल की कीमतों में और उछाल आ गया, यानी कि रूस ने तेल के प्रति यूनिट निर्यात से अधिक धन कमाया। रूस को कुल मिलकार आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचा।

प्रतिबंधों से रूस को घुटने टेकने पर मजबूर करने में विफल रहने से परेशान ई.यू. ने रूस के सैन्य अभियान को नियन्त्रित करने के नए तरीके लागू करने शुरू किए। उसने रूस के तेल की ब्रिकी की कीमत तय करने के बारे में सोचा, जिसे सम्बद्ध प्रतिबंधों के बिना लागू नहीं किया जा सकता था।

कीमत नियन्त्रण की प्रतिक्रिया में रूस ने अपने तेल निर्यातों को सीमित रखने के विचार को प्रसारित किया है। इससे तेल की वैश्विक कीमतें आसमान छू सकती हैं और समूची वैश्विक अर्थव्यवस्था में घबराहट पैदा हो सकती है। इससे वैश्विक वित्तीय बाजारों और उसकी लागतों पर विपरीत असर पड़ सकता है। तेल की कीमतों पर नई अनिश्चितता तब सामने आ रही है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की संभावनाओं को झेल रही है। यह स्थिति कुल मिलाकर सब कुछ अनिश्चित बनाती है।

तेल की कीमतों का कैसा भी उछाल वैश्विक मंदी के स्तर को और नीचे गिरा सकता है। खासतौर पर जब चीन गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है तो बड़ी पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की चर्चा हो ही है। रूस के तेल से मिलने वाला कोई अतिरिक्त झटका आर्थिक मंदी को और गहरा सकता है।

इस स्थिति को खराब होने से कुछ हद तक तभी रोका जा सकता है जबकि पश्चिम के अग्रणी देश, विशेषकर अमेरिका अन्य बड़े तेल उत्पादक देशों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए राजी करे ताकि रूस की तेल सप्लायी पर लगे प्रतिबंधों से ग्लोबल मार्केट्स से होने वाली कमी से निबटा जा सके।

ऑर्गनाइजेशन ऑफ पैट्रोलियम एक सपोर्टिंग कन्ट्रीज (ओ.पी.ई.सी. औवेक) परम्परागत रूस से तेल के बाजार में आने वाले किसी भी उछाल का लाभ लेती रही हैं। कीमत वृद्धि के कारण बाजार में और अधिक तेल बिकने के लिए आया।

हालांकि ओपैक देशों पर अपना दबदबा रखने वाला सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब के कूटनीतिक रिश्तों में आयी तलरवी के कारण सऊदी अरब ने रूस के साथ नए सम्पर्क स्थापित किए और ऐसा लगा जैसे कि वह तेल की कीमतें ऊंची रखने में रूस की कार्यवाही का समर्थन कर रहा है। अतः तेल की कीमतें स्थिर रहने की दूर-दूर तक संभावनाएं नहीं हैं क्यांकि मध्य पूर्व में अमेरिका के पूर्व सहयोगी सऊदी अरब ने ई.यू. द्वारा रूस के तेल की कीमत तय करने की प्रतिक्रिया में अपना तेल उत्पादन और सप्लायी बढ़ाने के अमेरिका के अनुरोध को मानने से इन्कार कर दिया है।

राहुल गांधी की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चल रहे हैं, उनसे क्यों बात कर रहें हैं?

स्वरा बातचीत में, वे उन मुद्दों को उठाती रहीं, जिन्होंने दूसरी और तीसरी श्रणियों को बहुत आहत किया है।

वस्तुतः, ऐसा प्रतीत हुआ है, मानो स्वरा उस व्यापक भारतीय पुनर्जागरण को स्वर दे रही हों, जिसकी गति मंद भले ही हो, जो लगातार हो रहा है।

स्वरा भास्कर, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के खुले वातावरण में पली-बड़ी हैं, को उनकी फिल्म "माधोलाल कीप वॉकिंग" से प्रसिद्धि मिली। ज्ञातव्य है कि स्वरा की माँ जे.एन.यू. में शिक्षिका थीं।

लेकिन स्वरा अब भी उसी चीज को कह रही हैं: "चलते रहो"। अब माधोलाल "राहुल गांधी" में बदल गया है, और इस बात पर जोर देने के लिये, वे राहुल के साथ पैदल चलीं। और जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, उन्हें उनका "पारिश्रमिक" मिल गया है। उन्होंने कहा, "और जहाँ तक भाजपा का संबंध है, उसके अधिकांश लोग घोर झूठे हैं।"

पायलट के उत्साही ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- पर यह भी सच है कि, मंगलवार को यात्रा के दौरान ज्यादा भीड़ नहीं थी। क्या यह जानबूझकर किया गया था, तथा पायलट विरोधी साजिश में व्यस्त मु.मंत्री के खेमे को भीड़ जुटाने की फुर्सत नहीं मिली। क्योंकि, जहां से यात्रा गुजर रही है, उसके अगल-बगल के दो जिलों के प्रभारियों को भीड़ लाने की जिम्मेवारी दी गई थी।

यह भी ज्ञातव्य है कि कोटा, शांति धारीवाल का निर्वाचन क्षेत्र है, जिनका अजय माकन द्वारा तैयार की गई अनुशासनहीनता की रिपोर्ट में नाम है और जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

शायद इसी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने निर्णय लिया है कि यात्रा ना तो कोटा में रूकेगी और ना ही लंच या किसी अन्य चीज़ के लिए इसका वहां ठहराव होगा। यात्रा कोटा में बिना किसी विश्राम के जारी रहेगी, यात्रा का पड़ाव कोटा के बाहर ही होगा। कार्यक्रम में यह बदलाव आज ही हुआ है।

सूत्र कहते है कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान या चाय के लिए रूकने के वक्त भी गहलोत से बातचीत नहीं कर रहे हैं।

समझा जाता है कि वे (राहुल) साफ तौर पर उनकी (गहलोत) उपेक्षा कर रहे हैं।

किन्तु कल राहुल गांधी उस समय अशोक गहलोत पर भड़क गये, जब पूरे यात्रा स्थल पर खाकी यूनिफॉर्म में बड़ी संख्या में पुलिस दिखाई दी। गहलोत की तरफ मुड़कर, राहुल गांधी ने कहा कि इतनी सारी पुलिस को हटाओ, वरना मैं घर लौट जाऊँगा।

इसके बाद, वर्दीधारी पुलिस तो हटा दी गई लेकिन उसके स्थान पर सामान्य वस्त्र पहने पुलिस कर्मी आ गये।

आज की यात्रा इस अर्थ में निराशाजनक रही कि यात्रा स्थल पर आम लोग बहुत ही कम संख्यचा में थे तथा उनके स्थान सरकारी मशीनरी, कांग्रेस कार्यकर्ता, यात्री एवं पुलिस कर्मी दिखाई दे रहे थे। लेकिन यह भीड़ उस राज्य के अनुरूप नहीं कही जा सकती, जहां कांग्रेस का शासन हो।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि या तो अशोक गहलोत जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी का शो फीका रहे, या फिर उन्होंने भीड़ जुटाने के लिय कोई प्रयास ही नहीं किये हैं क्योंकि मूल योजना के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया था कि रोजाना की भीड़ को लाने की व्यवस्था दो पड़ोसी जिलों के नेता करेंगे।

एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर आप अपनी ऊर्जा सचिन पायलट को नीचे लाने में लगा देंगे, तो कुछ सकारात्मक करने का समय और गुंजाइश ही कहाँ रहेगी।

सोनिया गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रंधावा पंजाब से हैं और उन्हें एक कठोर एवं सीधी बात करने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी।सूत्र कहते हैं कि रंधावा पार्टी हाईकमान के आदमी हैं। इसके साथ ही सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट का पक्ष लेने के कारण गहलोत ने अजय माकन को निशाना बनाया था। अब एक निष्पक्ष बात करने के लिए रंधावा को लाया गया है। राजस्थान में कांग्रेस के नए प्रभारी महासचिव आज शाम जयपुर आ रहे हैं, और उनके राहुल गांधी की यात्रा में कल शामिल होने की उम्मीद है। जब वे राहुल गांधी के साथ चल रहे होंगे तो राजस्थान पर अनिवार्य रूप से चर्चा हो सकती है। लम्बे समय से लम्बित यह निर्णय एक खुले घाव की भांति सड़ रहा है क्योंकि नेतृत्व राजस्थान के लिए कुछ तय नहीं कर पा रहा। लेकिन यात्रा के राजस्थान से गुजर जाने के बाद उम्मीद है कि राजस्थान को कोई समाधान पसन्द आएगा।

सरकार, डिस्कॉम व विद्युत नियमन आयोग की मिलीभगत से सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर्स को न्याय नहीं मिल रहा

हाई कोर्ट में आर.ई.सी. मकैनिज़्म के तहत बने सोलर ऊर्जा उत्पादको के अधिवक्ता ने कहा कि, इस मिलीभगत का प्रमाण है कि, तीनों (सरकार, डिस्कॉम तथा आयोग) जवाब में एक ही भाषा में एक ही तर्क प्रस्तुत करते हैं

- अधिवक्ता रवि चिनारिया का कहना है कि, 5 मार्च 2019 को आयोग ने यह तर्क दिया कि, आर.ई.सी मकैनिज़्म के तहत निर्मित प्लांट से मिल रही बिजली की दरें 3.14 रुपये प्रति यूनिट पर सीमित करी जाती है, जिस पर डिस्कॉम ने भी अपनी रजामंदी दिखाई थी और याचिकाकर्ताओं से अण्डरटेकिंग भी ली थी। परंतु लगभग चार साल बाद भी डिस्कॉम ने बिजली खरीदने के लिए पी.पी.ए. हस्ताक्षरित नहीं किया है और याचिकाकर्ताओं को बिजली उप्तादन के लिए भुगतान भी नहीं किया गया है।

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 6 दिसम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट में आज रिन्युबल एनर्जी सर्टिफिकेट (आर.ई.सी.) मकैनिज़्म के तहत सौर तथा पवन ऊर्जा में निवेश करने वाले निवेशकों की ओर से दायर करीब 108 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जैसा कि विदित है कि इस मामले में 1 अप्रैल 2019 से याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित सौर और पवन ऊर्जा के प्लांट से बिजली उत्पादित की जा रही है और राज्य सरकार के डिस्कॉम्स को भी दी जा रही है, परंतु इन्हें बिजली उत्पादन के लिये डिस्कॉम्स द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से कल भी अधिवक्ता संदीप तनेजा, सुकृति कासलीवाल और पुनीत सिंघवी बहस करेंगे।

इस मामले में लगभग डेढ़ महीने बाद पुनः सुनवाई शुरू की गई है क्योंकि न्यायाधीश एम.एम.श्रीवास्तव के परिवार में निधन होने के कारण वे मामले की सुनवाई नहीं कर सकते थे। आज सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रवि चिनारिया, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आई.ओ.सी.) और अन्य प्राइवेट पार्टी की ओर से पैरवी कर रहे थे, ने अपनी बहस पूर्ण की। सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिवक्ता रवि चिनारिया से यह कहा कि सरकार के वकीलों का कहना है कि उन्हें ओपन मार्केट में बिजली सस्ते दामों में मिल रही है इसलिये वह आर.ई.सी. मकैनिज़्म के तहत बने सौर ऊर्जा के प्लांटों से बिजली नहीं खरीदना चाहती है। उन्होंने रवि चिनारिया से पूछा कि डिस्कॉम सस्ती दरों पर बिजली खरीदे और फिर सस्ते दामों पर ही उपभोक्ताओं को बिजली बेचे, यह जनहित में लिया हुआ फैसला है और अदालत सरकार के फैसले में कितना हस्तक्षेप कर सकती है? इस पर रवि चिनारिया ने अदालत को कहा कि सरकार का यह कहना कि इससे सस्ती दरों पर ही बिजली मिल रही है, इस वजह से यह लाभ उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, यह मिथ्या है। डिस्कॉम कानूनी रुप से बाध्य है, इन बिजली उत्पादकों से बिजली खरीदने और प्रोत्साहन देने के लिए।

उन्होंने अदालत को बताया कि वर्ष 2003-04 में राज्य सरकार को थर्मल पावर प्लांट से 3.50-4 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलती थी, और यही बिजली राज्य सरकार 5-5.30 रुपये की दर पर रिहाइशी उपयोग के लिये उपभोक्ताओं को बेचती थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 तक राजस्थान एक "एनर्जी डेफिसिट" स्टेट था। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार का कहना है कि उसे ओपन मार्केट में वर्ष 2019 में करीब 2.85 रुपये प्रति यूनिट तक की दरें मिल रही हैं, परंतु आज की तारीख में रिहाईशी उपयोग के लिये दर 8-9 रुपये प्रति यूनिट है और व्यवसायिक उपयोग के लिये लगभग 15 रुपये प्रति यूनिट है। उन्होंने कहा कि बिजली की उपलब्धता तथा बिजली की दरें यह निर्धारित नहीं कर रही हैं कि उपभोक्ताओं को इसका कितना लाभ मिलेगा।

डिस्कॉम में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार ही महंगी दरों का कारण हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग चार वर्ष से डिस्कॉम्स ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं को एक रुपये का भुगतान भी नहीं किया है और उन्हें आज भी बिजली मिल रही है जिसे वे अन्य प्रदेशों की सरकार को बेच रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में डिस्कॉम्स की मॉनोपॉली बनाने के लिये राज्य सरकार ने उद्योगपतियों के लिये "ओपन एक्सेस" की सुविधा को विफल करने के लिये कई नये नियम कायदे लागू किये हैं। पाठकों को बता दें कि उद्योगपति "ओपन एक्सेस" यानी सौर ऊर्जा का प्लांट बनाकर स्वयं के लिये बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, परंतु राज्य सरकार ने इस नीति को विफल करने के लिये "ओपन एक्सेस" प्लांटों पर भारी "वीलिंग चार्ज" (यानी सरकार के ग्रिड का इस्तेमाल करने के लिये भारी फिक्स चार्ज) लगा दिये हैं। रवि चिनारिया ने कहा, फिक्स चार्ज की दरें बढ़ा दी हैं, जिससे प्रदेश में कोई भी केप्टिव पावर प्लांट लगाना नहीं चाहता और दिल्ली में स्थित पावर एक्सचेंज से बिजली भी नहीं खरीदना चाहता।

उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष इस मामले में कई तथ्य ऐसे हैं जिससे साबित होता है कि राज्य सरकार और उसकी डिस्कॉम और विद्युत विनियामक आयोग मिले हुए थे और इनकी मिलीभगत से ही 2019 से याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा उत्पादित बिजली का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अगस्त 2018 में सभी डिस्कॉम्स ने आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि "पूल रेट" मकैनिज़्म के तहत तय की गई दरों पर आर.ई.सी. मकैनिज़्म के तहत बने प्लांटों से बिजली नहीं खरीदेंगे। डिस्कॉम्स का कहना था कि "पूल रेट" (जो पिछले वर्ष डिस्कॉम्स द्वारा सभी स्रोतों से खरीदी गई बिजली का औसत है) पर बिजली खरीदना उन्हें महंगा पड़ रहा है। रवि चिनारिया ने अदालत को आगे बताया कि 5 मार्च 2019 को नियामक आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तय किया था कि वह आर.ई.सी. मकैनिज़्म के तहत निर्मित पावर प्लांटों के लिये बिजली की दर को 3.14 रुपये प्रति यूनिट पर सीमित कर रहे हैं और जो निवेशक आर.ई.सी. मकैनिज़्म से बाहर जाना चाहते हैं, उन निवेशकों के लिये दर 3.17 रुपये प्रति यूनिट पर सीमित रखी जाती है।

रवि चिनारिया ने अदालत को कहा कि उनके मुवक्किल ने आयोग के फैसले को मानते हुए सभी डिस्कॉम्स से "परचेज पावर एग्रीमेंट" (पी.पी.ए.) हस्ताक्षरित करने के लिये पत्र लिखा था और 29 मार्च 2019 को सभी डिस्कॉम्स को अंडर टेकिंग भी दे दी थी, परंतु जब नवम्बर 2019 तक डिस्कॉम्स ने याचिकाकर्ताओं के साथ पी.पी.ए. हस्ताक्षरित नहीं किये तब उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना ही पड़ा।

उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने आयोग के समक्ष भी याचिका पेश की थी परंतु तब डिस्कॉम की तरफ से यह तथ्य छुपाया गया था कि वह उनके मुवक्किलों के साथ पी.पी.ए.हस्ताक्षरित करना चाहते थे। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि आयोग ने दरें सीमित करने से पहले इससे संबंधित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने अदालत को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि डिस्कॉम्स और सरकार की तरफ से एक ही जवाब पेश किया गया है, परंतु हैरानी की बात है कि आयोग द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार व डिस्कॉम के जवाब से हूबहू मेल खाता है, जबकि आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो बिजली की दरें तय करता है और डिस्कॉम को बिजली खरीदने पर बाध्य भी कर सकता है।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908